STATUTORY RESOLUTION.....Contd.

Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the constitution in relation to State of Jharkhand

श्री धीरज प्रसाद साहू (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए अपनी ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जब से झारखंड राज्य बना है, तब से वहां अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है। अभी हमारे एक भाई हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनसे मेरा यह कहना है कि जब से झारखंड बना है और वहां जो बर्बादी हुई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ एनडीए का है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी भी सत्ता के लिए आगे नही आयी है। अगर वह सत्ता में आना चाहती, तो पिछली बार भी हम लोग सत्ता में आ सकते थे, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, वह बिल्कुल निराधार है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इन लोगों में से कई भ्रष्टाचारी लोग यहां पर हैं और वे मंत्री भी रहे हैं, जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, आज उनके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि सब कुछ है। आज अगर बड़ी-बड़ी जांच बिठायी जाए, तो इनके कई लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। महोदय, आज राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री धीरज प्रसाद साहू: आप चुपचाप रहिए, हमको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You will get the chance to speak. ...*(Interruptions)*...

श्री धीरज प्रसाद साहू: आज अगर जांच बिठायी जाएं, तो इनके कई लोग आज जेल में नजर आएंगे। आज जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जारहा है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You confine to the speech. ...*(Interruptions)*...

श्री धीरज प्रसाद साहू: महोदय, झारखंड में एक ऐसी परिस्थिति आयी, जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जब से झारखंड राज्य बना है, वहां अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है, लेकिन एनडीए के शासनकाल के दौरान वहां विकास का कार्य नही हुआ है, बल्कि अवैध खनन के द्वारा पूरे प्रदेश का दोहन हुआ है। जब से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां के लोगों को बदलाव नजर आ रहा है तथा वहां विकास के कार्य जोरों से चल रहे हैं। इसके लिए मैं वर्तमान राज्यपाल को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। झारखंड राज्य में बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने निजी ठेकेदारों के माध्यम से निजी एरिया के बाहर फॉरेस्ट एरियाज़ में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से करा रही हैं। अवैध खनन के कारण जंगलों को उजाड़ा जा रहा है और इस संदर्भ में कई बार मैंने वहां के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और वहां के प्रशासन को भी खबर दी है, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, वहां विकास की बात की जाती है, लेकिन जो खनिज सम्पदा झारखंड में सबसे ज्यादा पायी जाती है, उसका सबसे ज्यादा अवैध खनन इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक थर्मल पावन प्रोजेक्ट, जो चंदवा में लगना था, उसे इस राष्ट्रपति शासन के दौरान ही जल्द खोला जाए, क्योंकि उसके खुल जाने से वहां के ग्रामीणों की रोजगार और विद्युत की समस्या दूर होगी।

महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना है कि खनिज सम्पदा से भरपूर लोहरदगा जिला झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर हिंडाल्को और कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के खनन क्षेत्र हैं। यह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लोहरदगा से यहां तक की रेल लाइन ब्रॉडगेज हो चुकी है। मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना है, जिससे रेलवे के द्वारा लोहरदगा एवं पड़ोसी जिलों के लोगों की जनसुविधाओं में इजाफा हो सके। पहला यह है कि लोहरदगा जिले में रेल लाइनों का विद्युतीकरण जितनी जल्द हो सके कराया जाए। लोहरदगा से कोलकाता के बीच लोगों की ट्रेन की मांग है। गुमला-पलामू परिमंडल के जिलों के निवासियों को कोलकाता जाने के लिए पहले रांची पड़ता है। तीसरा है, लोहरदंगा के बीच रेल लाइन का काम तेजी से कराया जाए।

पूर्व रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा कोरबा-लोहरदंगा के बीच रेल लाइन के परिचालन की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को धरातल पर लाना है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाना है, ताकि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच रेल लाइन सेवा शुरु की जा सके। झारखंड के अधिकतर जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिससे विकास बाधित होता है। इसको हमें गंभीरता से लेने की जरुरत है और नक्सल प्रभावित लोगों को मुख्य धरा में लाने के लिए विशेष सहायता प्रारम्भ करनी चाहिए। डी0वी0सी0 एवं कोल इंडिया का मुख्यालय रांची में होना चाहिए, क्योंकि इन कम्पनियों का अधिकतर कार्यक्षेत्र झारखंड है। झारखंड में पर्यटन की बहुत सम्भावनाएं हैं। इसके लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I stand here to highlight the tragedy of Jharkhand. Jharkhand is one of the richest States in India in mineral

[Shri D. Bandopadhyay]

resources, but Jharkhand people have the poorest *per capita* income in India. This contradiction shows that the people of Jharkhand are not given change to properly administer themselves through their elected representatives. I don't know exactly the number, but in the last one decade, more than half a dozen times President's Rule has been imposed there. President's Rue under article 356, is in part XVIII of the Constitution, the heading of which is 'Emergencies'. It appears that Jharkhand has been under Emergency for the last one decade. What sort of democracy are we running there? It is because of lack of democracy that people are suffering there. It is because they have no say in the governance of the State that they are suffering. Sir, there may be Presidential Rule for other reasons. I don't know.

But the point is we should have an elected Government in Jharkhand as soon as possible so that people can govern themselves through their own elected representatives. It doesn't matter whom they elect; it doesn't matter which party they belong to. They are to be properly elected by the people by free expression of their voting right. So, Sir, while what happened have happened, I would urge, through you, to the Government that restoration of the elected body is necessary by having fresh elections and having another elected Government there. Emergencies are emergencies. Emergency cannot be normalcy. Therefore, Sir, I appeal, through you, to the Government to restore democracy in Jharkhand as early as possible. Thank you.

श्री संजीव कुमार (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, 15 नवम्बर, 2000 को तीन राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। महोदय, जब झारखंड का गठन हुआ एक ही दिन 15 नवम्बर को, तो जब पेंशन लाइबिलिटी फिक्स करने की बात आई, झारखंड के साथ दे अन्य राज्य जो उसी समय अलग हुए थे, उनके लिए अलग मापदंड बना कि पेंशन लाइबिलिटी फिक्स होगी पोपुलेशन रेश्यो के आधार पर, लेकिन झारखंड के केस में यह तय हुआ कि नम्बर ऑफ एम्पलॉइज को रेश्यो बनाया जाएगा और अभी फिलहाल केन्द्र सरकार की चिट्ठी आई है कि झारखंड को 2584 करोड़ रुपए बिहार को देने होंगे। उस समय एन0डी0ए0 की सरकार थी। 1956 से लेकर आज तक जितने भी राज्य बने हैं, उनमें जब पी पेंशन लाइबिलिटी डिसाइड करने की बात आई, तब बराबर यह हुआ कि पापुलेशन रेश्यो को आधार बनाया जाएगा।

महोदय, झारखंड के केस में अलग मापदंड क्यों? मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि

क्या झारखंड सब से अलग राज्य है? जब देश में कोई कानून बनता है तो क्या वह और राज्यों के लिए अलग होगा और झारखंड के लिए अलग होगा? महोदय, झारखंड के साथ बराबर भेदभाव हुआ है जबकि झारखंड देश को टोटल कोयला भंडार का 25 से 37 परसेंट कोयला देता है, झारखंड 25 परसेंट आयरन और देता है, ताम्बा और बहुत से मिनरल्स देता है। झारखंड के ट्राइबल्स, जोकि बिरसा मुंडा और सिदूकानू की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आजादी से पहले तक से लड़ रहे हैं, वहां आज हालत यह है कि झारखंड की सवा तीन सौ करोड़ की टोटल पॉपुलेशन में से 16.6 प्रतिशत पॉपुलेशन अलग-अलग राज्यों में माइग्रेट कर चुकी है। महोदय, मैंने आज ही आपके संज्ञान में लाया था कि तीन संथाल ट्राइबल्स जोकि पंजाब में टेली पावर कॉम में काम कर रहे थे, उनकी 23 तारीख को लाशें भेजी गयीं और उन्हें मुआवजे के नाम पर सिर्फ 20 हजार रुपए दिए गए। यह पूरे देश के ट्राइबल्स के साथ अन्याय है, उनकी insult है।

महोदय, झारखंड की सरकार क्यों गिरायी गयी? जब वहां बी0जे0पी0 की सरकार थी और बाबूलाल मरांडी मुख्य मंत्री थे, उस समय Pension Liability Bill पार्लियामेंट से पास हुआ था। महोदय, आज तक झारखंड के विषय में, जोकि पूरे देश का सबसे अधिक मिनरल्स और कोयले से भरा प्रदेश है और केन्द्र सरकार को सभी चीजों से fulfill करता है, उसकी व्यवस्था पर उस समय किसी ने नहीं बोला। इस बारे में न कांग्रेस ने बोला और न बीजेपी ने बोला।

महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विस्थापन झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। आज तक जितने भी बोकारो स्टील सिटी बने, उस समय 34 हजार एकड़ जमीन ली गयी और जरुरत थी सिर्फ 12 हजार एकड़ की, बीसीसीएल बना, सीसीएल बना, ईसीएल बना, दुमका में मसांजोर डैम बना या पैनम प्रोजेक्ट बना जिसके चलते पंजाब को कोयला दिया जा रहा है और वहां पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है। इन सभी जगहों पर जहां कोयला दिया गया, खनिज दिया गया- वह जमीन ट्राइबल्स की है, जिस के अंदर से कोयला निकलता है और जिस के अंदर से खनिज निकलता है। महोदय, वहीं के ट्राइबल्स दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं और अगर ट्राइबल कहीं मरता है तो उसकी कीमत 20 हजार रुपए दी जाती है जबकि झारखंड में ट्राइबल लैंड पर दूसरे राज्य से जो लोग आते हैं, वे लोग करोड़पति बनते हैं और हमारे यहां के ट्राइबल्स दूसरे राज्यों में maid servant का या नौकर काम करते हैं। महोदय, प्रश्न यह है कि आज तक झारखंड का कोई ट्राइबल, जिसकी जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता है, जिसकी जमीन के नीचे से ताम्बा निकाला जाता है, जिसकी जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता है, करोड़पति क्यों नहीं बना? आज तक कोई सोरेन, टिड्डू, मुरमू या कोई मुंडा करोड़पति क्यों नहीं है? महोदय, ट्राइबल्स जिनकी जमीन है, जिन की धन-सम्पदा है, जिनका जंगल है, वे माइग्रेट कर के पंजाब में जा रहे हैं और वहां मर रहे हैं। मोहदय, हाल में चैन्नई में माइग्रेट कर गए ट्राइबल्स मरे हैं। महोदय,

[श्री संजीव कुमार]

दिल्ली का कोई ऐसा household नही है, जहां पर ट्राइबल नौकर या maid servant नही है और बात की जाती है हमने झारखंड का उत्थान कर दिया है, हमने झारखंड में सड़कें बिछा दी और झारखंड में रेल लाइंस बिछा दी। महोदय, झारखंड में कुछ नहीं हुआ है। अगर झारखंड में आज तक कुछ हुआ है तबाही हुई है। अभी कहा रहा था कि CBI/Enforcement Directorate के डर से हम लोगों ने सरकार गिरा दी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने single handedly बिरसा मुंडा और सिडोकानो बाद फाइट की और अपनी ताकत पर सेपरेट झारखंड स्टेट बनायी। शिबू सोरेन कभी CBI/Enforcement Directorate से नहीं डरे हैं और शिबू सोरेन पर आज कोई केस नहीं है। शिबू सोरेन के खिलाफ झारखंड मूवमेंट के दौरान बहुत केस हुए थे- चिरुडिनर नरसंहार केस, कुरको नरसंहार केस, शसीनाथ झा मर्डर केस, लेकिन वे सब में acquit हो चुके हैं और उनमें से कुछ केस CBI ने investigate किए थे। एक केस जिस मे acquittal के against अपील है, जोकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वरना शिबू सोरेन पर कोई केस नहीं है। अगर सौ केस भी रहेंगे तो शिबू सोरेन किसी भी सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से डरते नहीं हैं। इसलिए सरकार गिराने का कारण यह है कि झारखंड में जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनायी गयी थी, वे उम्मीदें fulfill नहीं हो रही थीं

समन्वय के लिए कॉऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था, मगर कहीं पर भी कॉऑर्डिनेशन का कोई साइन दिखाई नहीं पड़ रहा था। सोचा गया था कि झारखंड के लाग जो विस्थापित हो रहे हैं, उस विस्थापन को रोका जाएगा, लेकिन विस्थापितों का पलायन बिल्कुल बंद नही हुआ। झारखंड जो पूरे देश को मैक्सिमम कोयला, तांबा, लोहा और अन्य खनिज पदार्थ दे रहा है, जब उस झारखंड के लोग दूसरो राज्यों में गए, तो उन दूसरी जगहां पर इनकी इन्सल्ट हुई और जब कोई वहां मरता है तो उसकी कीमत बीस हजार रुपए लगाई जाती है। यह स्थिति झारखंड की है। हम चाहते थे कि विस्थापन रुके, हम चाहते थे कि झारखंड तरक्की करे, हम चाहते थे कि झारखंड में आदिवासी जल, जंगल और जमीन से वंचित न हों। झारखंड बनने के बाद अभी 79 एमओयू साइन हुए हैं। बहुत लोगों को कोल की लीज दी जा रही है। मैं जयराम रमेश जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने झारखंड की समस्या को एटलीस्ट सोचने, समझने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे लगा कि झारखंड में अभी कुछ उम्मीद बाकी है, मगर यह विस्थापन की समस्या झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है।

महोदय, झारखंड से सरकार क्यों गिराई गई है? इस पर कहने जाएं, तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं लॉयर हूं, मैं भी जानता हूं कि 356 क्या होता है, किस हालात में 356 लगता है? मैं आपके माध्यम से पूरे सदन में यह बात बताना चाहता हूं कि यदि थोड़ी सी गुंजाइश है कि यदि बिना किसी ब्लेकमैलिंग के, बिना किसी ऐसी बात के सरकार बन सकती

3.00 P.M.

है तो कोशिश चाहिए, नहीं तो झारखंड विधान सभा को भंग करके चुनाव करवाने चाहिए। ऐसी मेरी राय है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Ram Kripal Yadav. You have three minutes. Try to conclude your speech in three minutes.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार से झारखंड का बंटवारा सन 2001 में हुआ था और झारखंड का बटवारा इसलिए हुआ था कि झारखंड में जो खासकर के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, गरीब तबके के लोग, हैं उनका उत्थान हो। यह उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के वे शोषित और पीड़ित लोग, जिनका वर्षो से लगातार दोहन और शोषण होता रहा है उनकी तरक्की होगा, विकास होगा, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की सही सुविधा होगी, उनके पीने के पानी की समस्या दूर होगी और जो सबसे बड़ी समस्या वहां नक्सलवाद और उग्रवाद की है उससे मुक्ति मिलेगी। इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर के बिहार से झारखंड से बंटवारा हुआ था।

महोदय, आज बिहार से बंटवारे के बाद झारखंड में क्या हालात हैं? वहां कोई भी सरकार स्थिर नहीं रही और स्थिर न होने की वजह किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जो बड़ी पार्टी हैं। कई पार्टियों के मिलन के बाद और खासतौर से निर्दलीयों के मिलन के बाद सरकार का निर्माण होता रहा। मैं समझता हूं कि झारखंड राज्य के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का कारण भी बना। वहां जिन लोगों का भी शासन हुआ, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने वहां राज किया, मगर जो झारखंड के बंटवारे के मूल उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। वहां जो गरीब तबके के लोग थे, जिनका सैंकड़ो वर्षों से शोषण हो रहा था, वह शोषण होता रहा। यह कहा जाता है, जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है। झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झारखंड तो अमीर राज्य है, पर वहां के लोग गरीब हैं। उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अगर न्याय हुआ होता, अगर उनके द्वारा जो चुनी गई सरकार थी, उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं बनी थीं, अगर उनका इंप्लीमेंटेशन समय पर हुआ होता, तो शायद झारखंड की तकदीर चमक गई होती और झारखंड, देश का सबसे अमीर प्रदेश होता।

हमारी पार्टी के नेता लालू प्रसाद जी, जो उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वे इस पक्ष में थे कि बिहार का बंटवारा न हो। चूंकि यह तर्क दिया गया था, यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद वहां के लोगों की और दुर्गति होगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your time is over.

श्री राम कृपाल यादव: आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPAN): Try to conclude.

श्री राम कृपाल यादव: चूंकि मैं बिहार का वासी हूं और झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा.ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन): अब आप कनक्लूड करिए।

श्री राम कृपाल यादव: अगर आप सहमति नहीं देंगे, तो वहां की स्थिति की जानकारी इस सदन को और देश को नहीं मिल पाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You come to the point.

श्री राम कृपाल यादव: मैं यह कह रहा था कि झारखंड राज्य बनने के बाद सत्ता में आने के लिए जो लड़ाई थी, बिहार का बंटवारा हो जाए झारखंड से, इसलिए कि वे इसे अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, झारखंड की संपत्ति को लूटना चाहते थे और सचमुच में यही हुआ। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे थे झारखंड में कुछ हुआ है, तो लूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां उसे अपना उपनिवेश बनाकर, वहां की संपत्ति को लूटकर अपनी पार्टी को फीड करने का काम किया है। अभी यहां लंबी-चौड़ी बातें कही जा रही थीं ...**(व्यवधान)**... यह बात सही है कि झारखंड में जितने घोटाले हुए हैं, जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जितनी लूट हुई है, अगर आज भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई जाए, तो सारे के सारे मुख्य मंत्री और मंत्री जेल में नज़र आएंगे। आज भी कई मंत्री जेल में हैं, जो पूर्व मंत्री हैं या विधायक हैं, वे जेल की सीखचों के पीछे हैं। यह दुर्भाग्य है कि आज भी झारखंड के लोग, जिनका हक था, वे देश के विभिन्न भागों में ईंटों के भट्ठे पर काम कर रहे हैं। जो हमारी मां है, जो हमारी बहनें हैं, जिनके लिए अलग झारखंड राज्य बना था, जिनके लिए केन्द्र सरकार ने पैसा देने का काम किया, लेकिन वह पैसा उन तक नहीं पहुंचा, वह पैसा चंद लोगों की पॉकेट में पहुंच गया। आज झारखंड एक उपनिवेश बन गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude.

श्री राम कृपाल यादव: मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि झारखंड मेरा भाई था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है,

मजबूरी थी, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं था। वहां की राज्य सरकार अल्पमत में आ गई थी, प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2014 तक चुनाव हाने हैं, समय बचा हुआ है, सरकार ने मौका दिया कि आप लोग बैठिए, विचार करिए, क्योंकि केन्द्र सरकार नहीं चाहती है कि वहां राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रपति शासन तो मजबूरी में लगाया गया है, क्योंकि सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। साथ ही सरकार यह चाहती है कि वहां राज्य सरकार बने, वह उनको मौका दे रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Jai Prakash Narayan Singh. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। It is my last point. मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके हाथ में शासन है और आप सचमुच में चाहते हैं कि वहां सरकार बने। मैं जयराम रमेश जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने बहुत मंत्रियों को देखा है, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से झारखंड के विकास में रुचि ली है। ये गांवों में, जंगलों में जा रहे हैं, नक्सलवाद की परवाह किए बिना गांवों में संपर्क कर रहे हैं। वे लोग इनका थैंक्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में झारखंड के लोगों के प्रति दर्द है, उन आदिवासियों के प्रति दर्द है, कमिटमेंट है ...**(व्यवधान)**... मैं समझता हूं कि ओडिशा के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, पूरे देश के लिए है, लेकिन ये झारखंड में कुछ ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, लगाएं। मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में शासन और सत्ता आई है, आप इस समय का लाभ उठाइए। अगर सही मायने में, माननीय गृह मंत्री जी, आपको झारखंड का विकास करना है, तो जो राशि वहां पर गई है, उसका सदुपयोग कीजिए, लूट को बंद कीजिए और झारखंड के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो आज भी hand to mouth हैं, बिना शिक्षा के हैं, बिना बिजली-पानी के हैं, बिना सड़क के हैं, उनको पूरी ईमानदारी तथा वफादारी के साथ आप न्याय देने का काम कीजिए। वहां के महामहिम राज्यपाल पर झारखंडवासियों को पूरा भरोसा है और आप उनको सुविधा उपलब्ध कराइये। आपको जो मौका मिला है, उसमें आप एक नया इतिहास बनाने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं यह भी कहना चाहता चाहता हूं कि अगर सरकार बनने की संभावना नहीं लगती है, तो आप वहां पर चुनाव करिवाइये।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Yes, Mr. Yadav, You have made your point. Now, Shri Jai Prakash Narayan Singh

श्री राम कृपाल यादव: आप वहां पर समय से चुनाव करवा दीजिए, ताकि वहां पर चुनी हुई सरकार बन जाए और शासन करने का काम करें। सर, झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि ...**(व्यवधान)**... अगर झारखंड को बर्बाद करने वाली कोई पार्टी है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है, इसने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Jai Prakash Narayan Singh, try to confine to the time limit.

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने दिया है। मुझे माननीय सदस्य की बात सुनकर यह अहसास होता है कि इन्हें इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं है। ये इतिहास पढ़े और देखें कि किस पार्टी के कितने लोग आज जेल में bungling में बंद हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSAN NATCHIAPPAN): Please cooperate. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: किस पार्टी के कितने लोग आज जेल में बंद हैं, इसकी तुलना करके देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जेल में बंद हैं, इसका हिसाब आप पहले दे दीजिए, तब आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप गर्वनर शासन की मांग करते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (ओडिशा): भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेल में बंद हुए हैं। ...**(व्यवधान)**... अभी के प्रेसिडेंट को भी भ्रष्टाचार के कारण पद छोड़ना पड़ा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: आप सही बात बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप सही बात नहीं जानते हैं। आप टाइम-पास करने के लिए समय मत बर्बाद कीजिए। ...**(व्यवधान)**... भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि आपकी बात से वह डर जायेगी। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: गलती आप करें आर सज़ा हम भुगतें, ऐसा होने वाला नहीं है। ...**(व्यवधान)**... गलती ये लोग करें और सज़ा भारतीय जनता पार्टी भोगे, ऐसी कमजोर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। माननीय सदस्य इस बात को समझ लें कि चोरी ये करेंगे और जेल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जायेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपने निर्दलीय पार्टी के एक व्यक्ति को, सिंगल पार्टी के व्यक्ति को झारखंड का मुख्य मंत्री बना दिया और उसने पांच-छह हजार करोड़ रुपये की bungling की और जेल में अपनी पूरी केबिनेट के साथ बंद है। इसका दोषी कौन हैं, यह यादव जी बतावें। इसके लिए दोषी कांग्रेस है और सरकार बनाने वाली तमाम पार्टियां हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं थी। उनमें आरजेडी थी, उनमें कांग्रेस थी, यादव जी, इस बात का जवाब तो दें। ...**(व्यवधान)**... आप मधु कोड़ा जी को जेल से निकलवाइये, तब जाने कि आप लोग मर्द हैं। ...**(व्यवधान)**... ऐसी बात नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: सर, मुझे जवाब देने के लिए समय दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please cooperate. ...*(Interruptions)*... Kindly hear him. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: आपने सरकार को सपोर्ट करके निर्दलीय को पांच-छह हजार करोड़ रुपया लुटवा दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि जब दूसरे माननीय सदस्य बोले थे तब हमने उनके बोलने पर कोई व्यवयधान नहीं डाला, अब हमारे सम्मानित सदस्य को बोलने दीजिए। जब सच्चाई सामने आ रही है, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है। सर, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly hear him. ...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय श्री भुपेन्द्र यादव जी ने इस बात को रखा कि वहां पर पांच मुख्य मंत्री बदल गये और चार बार राष्ट्रपति शासन भी लग गया, यह हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है। अभी जेएमएम के नेता बोल रहे थे, ये भी कहते थे कि अगर नहीं हो सकता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तमाम पार्टी के नेता कहते थे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन मत लगाइये, वहां पर चुनाव कराइये। इनको चुनाव कराने में संकट क्या है, जबकि हमारे देश में प्रजातंत्र है।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

जब मुख्य मंत्री ने सत्ता में रहते हुए केबिनेट से पास कराकर दे दिया कि आप चुनाव कराइये, विधानसभा भंग कीजिए, सरकार के लिए बहुमत आने दीजिए, जनता जिसको चुनती है, उसकी सरकार बनने दीजिए, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि वहां पर सरकार बने। उसे पता हे कि हमारी पार्टी जीतकर नहीं आयेगी, तो दूसरी पार्टी की सरकार क्यों बने, वे दूसरी पार्टी की सरकार देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रखो।

मान्यवर, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ तो राज्य के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पेंशन तय की गई, जब कि पूरे देश में पॉपुलेशन के आधर पर पेंशन तय की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड में कर्मचारियों के बेस पर पेंशन क्यों तय हुई? आपने झारखंड के ऊपर दो हजार करोड़ रुपए का अधिभार डाल दिया। हम इस अधिभार को कहां से पूरा करेंगे? हमारी उचित मांग पूरी नहीं होती है और न ही हमारी उचित राशि हमारे प्रदेश झारखंड को मिलती है। हम नक्सल प्रभावित एरिया से ग्रसित हैं। ...**(व्यवधान)**...

[श्री जय प्रकाश नारायण सिंह]

लेकिन अगर यह सोच बाद में आई, तो उसमें सुधार होना चाहिए। चाहे गलती किसी की तरफ से भी हो, उस गलती को झारखंड की जनता क्यों भोगेगी? चाहे सरकार हमारी रहे या आपकी रहे, लेकिन liability तो झारखंड पर है। अगर वास्तव में यह अन्याय है, तो यह अन्याय झारखंड के साथ नहीं होना चाहिए। जो काम देश में अन्य राज्यों में किया गया है, वही काम झारखंड में भी होना चाहिए। धन्यवाद।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड): सर, मेरा नाम भी है।

MR. CHAIRMAN: I do not have your name. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Let him speak.

MR. CHAIRMAN: Take two minutes.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू: सभापति महोदय, मैं अपने साथियों की बातें सुन रहा था। महोदय, मैं सदन के सामने सिर्फ एक चित्र रखना चाहता हूं, उसके बाद बहुत सी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। यह झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जिसको बारह साल के कालखण्ड में तीन बार राष्ट्रपति शासन के स्वाद को चखने का मौका मिला। जब शिबू सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय तमाड़ बाइ-इलेक्शन हारने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। वर्ष 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब सरकार बनी थी। माननीय शिबू सोरेन की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सरकार में रहते हुए राष्ट्रहित में कांग्रेस के न्यूक्लियर डील के बिल का समर्थन किया था। उसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया और उसके बाद शिबु सोरेन की सरकार गिर गई थी। इस तरह से झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसके ठीक तीन महीने (ग्यारह दिन) बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था, उसने फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाकर यह दावा किया कि हमारे नेता मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब शिबू सोरेन जी की सरकार थी तब भी इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन वापस लिया था। यह तो इसका करेक्टर BJP का है। यह सत्ता के बिना रह नहीं सकती है।

तीसरी बार जब 2009 में चुनाव हुए थे तो तीन अलग-अलग पार्टियां थीं। उनमें बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग लड़ रहा था और हम अलग चुनाव लड़ रहे थे। सन् 2009 में सबसे बड़े घटक दल के रुप में हमारी पार्टी उभरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नही थे। हमने सरकार नहीं बनाई थी। उस समय हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं थी। हम चाहते थे कि झारखंड का विकास हो। उस समय इन दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़े थे, इसके बावजूद BJP ने गठबंधन किया जो कि एक बेमेल का गठबंधन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने उस समय सत्ता के लालच में

सरकार बनाई थी। इन्होंने गठबंधन किया और एक एग्रिमेंट किया कि हम 28-28 महीने शासन करेंगे। पहले बीजेपी ने मौका लिया और जब 28 महीने बीत गए तो स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कहा कि अब हमारी बारी है। क्योंकि दोनों के पास 18-18 सदस्य हैं, इसलिए हमें भी मौका दीजिए। मगर उन्होंने यह breach of contract किया, उन्होंने बेईमानी की और सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया, जिसके चलते आज यह स्थिति है। इसको यों कह सकते हैं कि बीजेपी की सत्ता लोलुपता के कारण तीनों बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। आज ये भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं बहुत से लोग जेल में हैं। अगर आपको याद हो तो झारखंड बनने के बाद सबसे पहले बीजेपी को राज करने का मौका मिला था।

इसके सबसे पहले मुख्य मंत्री BJP बाबू लाल मरांडी जी थे। उन्होंने अपने शासन काल में पब्लिकली कहा था, मीडिया में कहा था, चाहें तो आप पता लगा लें, कि इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि हमें रात में नींद नहीं आती है। मुख्य मंत्री रहते हुए इन्हें पता चल गया था, बी.जे.पी. को पता चल गया था कि इस राज्य में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। मगर उसके बाद भी हुआ क्या? उसके बाद चाहे अर्जुन मुंडा जी भी आए, उन्होंने उसी को खाद-पानी दिया और उसको बढ़वाया। अभी जो मधु कोड़ा की बात कर रहे थे, जो मंत्री जेल में हैं, वे कौन लोग हैं? वे उन्हीं के साथी हैं। वे उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे हैं, वे हमारे साथ नहीं रहे हैं। उनको छोड़ने के बाद हम लोगों ने बाहर से समर्थन दिया था। जब यह जानकारी मिली कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं, तब हम लोगों ने विरोध भी किया था। वे आपके साथी थे, हमारे साथी नहीं थे। हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों में कोई भी जेल में नहीं है। हम बता दें कि आप थोड़े दिन और रुकिए, यदि हम गलती से सरकार में आ गए, और अगर जांच हो गई तो आधे से ज्यादा लोग जेल में होंगे। आपने जो झारखंड में तिहाड़ जेल बनाई है, आप लोग उसी में चले जाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू: अभी तो माननीय मंत्री जयराम जी यहां पर हैं। हम उनको बहुत धन्यवाद देंगे कि मंत्री जी ने ऐसे-ऐसे गांवो में, जंगलों में जाकर रात बिताई है, जहां पर हमारे मुख्य मंत्री या कोई मंत्री भी नहीं गए हैं। जब ये जाते हैं, तो इतना भी नहीं होता कि मुख्यमंत्री जी उनके साथ में जाकर रात गुजारें। ये वहीं पर स्पॉट पर खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं भई, इनको इतना पैसा सैंक्शन कर दो। वे अभी सरंडा जंगल में गए थे, उन्होंने वहीं पर रहते हुए 280 करोड़ की सैंक्शन दे दी कि काम करो। ये रोना रोते हैं कि केन्द्र सरकार हमारी मदद ही नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की मदद करती है, उत्तराखंड की मदद करती है, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, मगर जब झारखंड की बात करते हैं तो मदद नही करती है। 12 साल में से 10 साल आपको सरकार चलाने का मौका मिला है। आपको उसके बाद का हिसाब देना पड़ेगा कि इन 12 सालों में आप राज्य को कहां ले गए? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू: सभापति जी धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशीलकुमार शिंदे: सभापति महोदय, मैं बहुत गौर से सभी साथियों के भाषण सुन रहा था। मैंने प्रसाद साहू जी से लेकर डॉ. बामुचू जी तक सभी के भाषण सुने। मैं भी इसका एक साक्षी हूं, जब एन.डी.ए. के वक्त 3 राज्य बायफर्केट किए गए थे, तब छोटे राज्य में एक अच्छी प्रजातांत्रिक सत्ता की सरकार आ जाएगी, राज्य अच्छी तरह से चलेगा, ऐसा पूरे देश को लगता था, लेकिन झारखंड एक ऐसा उदाहरण बन गया, जहां पर सरकारें नहीं चल रहीं। वहां पर सरकारें नही चलती रहीं और एक पार्टी भी नहीं आती रहीं। श्री राम कृपाल जी ने जो कहा, वह ठीक है यह पहले बिहार का अंग था और वहां पर काफी खनिज सम्पत्ति है। मैं पावर मिनिस्टर था, वहां पर कोयले की बहुत बड़ी खानें ही खानें हैं, भंडार हैं। हम चाहते थे और समझते थे कि झारखंड देश का एक सबसे रईस राज्य बन जाएगा, क्योंकि जब से भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तब से भूटान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। हम ऐसा ही चाहते थे, लेकिन यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय दूसरा ही काम चलता रहा। मैं टीका-टिप्पणी नहीं करुंगा, लेकिन मैं यादव जी को बताना चाहूंगा कि जब 11 Sep. 2010 में आपकी सरकार आ गई, तब उसके पहले भी वहां पर राष्ट्रपति शासन था। यह राष्ट्रपति शासन 1.6.2010 में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन कब हटा? 11.9.2010 को। और क्लेम करने कौन आ गए? भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम। यदि सरकार के दिल में ऐसा होता तो हम किसलिए राष्ट्रपति शासन को निकालते और उस वक्त आपके हाथ में सत्ता देते? सरकार इस तरह की दृष्टि कभी नहीं रखती। हम तो चाहते हैं कि वहां प्रजासत्ता की सरकार चले। आज तक वहां यह चली है। क्या हम जेएमएम को बोलने गए थे कि तुम उनकी सरकार खींच लो? एक कोएलिशन सरकार चलाना बहुत कठिन काम होता है। डा. मनमोहन सिंह जी यह सरकार कैसे चला रहे हैं, यह इस देश में एक मिसाल है। यह बहुत कठिन काम होता है। 5-5 मिनट में यहां तकलीफ होती है। यह नहीं सुना, तो निकले। सरकार चलाना एक बहुत कठिन काम होता है। उसे चलाने की ताकत रहनी चाहिए। सत्ता ऐसे नहीं मिलती है, बहुत कष्ट से सत्ता मिलती है। उसे टिका कर रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं हमारे सदस्यों से कहूंगा कि यादव जी और दूसरे सदस्यों पर मेरा कोई रोष नही है। यह सत्य घटना है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस देश में इस तरह के छोटे-छोटे राज्यों में ऐसा बिखराव हो जाए और इस देश को हमारी प्रजासत्ता का एक दूसरा दर्शन मिल जाए।

अभी हमारे साहू जी पूछ रहे थे कि नॉर्थ कर्णपुरा का क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भी उसमें थोड़े से साथी थे कि एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1997-98 में वहां पॉवर प्रोजेक्ट के लिए शिला रखी थी। उसके नीचे पूरा कोयला ही कोयला भरा हुआ है। हमारे मंत्री जी उसमें ऑब्जेक्शन ले रहे थे। मैं उनको बार-बार कहता था कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उन्होंने वहां शिला रखी है, तो उसको

परमिशन देनी चाहिए, चाहे वह बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन उनकी बात यह थी कि वहां इनवायरेनमेंट की प्रॉब्लम थी। वहां खदान में जितना नीचे जाएं, वहां बहुत ज्यादा कोयला मिलता था। मैं आपको और साहू जी को बताना चाहूंगा कि डा. मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने 8 दिन पहले निर्णय ले लिया है कि नॉर्थ कर्णपुरा में पॉवर प्रोजेक्ट होगा और यह उस तरह का होगा, जिस तरह उन्होंने कल्पना की थी। उस वक्त हमने नहीं देखा कि वे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, हम इसे क्यों दे दें, इसे कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश के डेवलपमेंट के जो सवाल होते हैं, उनमें पार्टी की बात नहीं लानी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, चाहे और दूसरी हो। घटना हो गई, तो हो गई। यहां अभी कांग्रेस की सरकार है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। गवर्नर साहब ने 3 दिन प्रयास किया कि यहां 356 नहीं लगे। उन्होंने सबको बुलाया। कांग्रेस ने यह कहा कि हम सरकार नहीं बना सकते। हमारे पास बड़ी संख्या थी, लेकिन हम सत्ता के पीछे नहीं भागे। हमने सत्ता छोड़ दी और कह दिया कि हम सरकार नहीं बना सकते। अभी भी वहां सस्पेंडेड एनिमेशन है। यादव जी, आप कह रहे थे कि वहां लोग मांग रहे हैं, स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। जैसा पहले हुआ था कि 3 महीने में सस्पेंडेड एनिमेशन हटा दिया गया, वैसा हो सकता है। लेकिन उसमें जिस तरह सरकार चलाने की और लोगों को साथ लेकर चलने की विल चाहिए, वह रहनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहाने आप सबको वहां के डेवलपमेंट के बारे में बोलने का मौका मिला। हम आपको झारखंड के बारे में आश्वस्त करते हैं, वहां जो भी पार्टीज़ हों, जो भी वहां के रहने वाले हों, कि वहां सुविधा देने के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम जो रिजोलुशन लाए हैं, आप उस रिजोलुशन को मान्य कर दीजिए।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Resolution to vote. The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

The motion was adopted.